

राजनीतिका अपराधीकरण

प्रलिस के लयि:

एमकिस कयूरी, जनप्रतनिधित्व कानून, राजनीतिका अपराधीकरण।

मेन्स के लयि:

राजनीतिका अपराधीकरण का कारण, प्रभाव और समाधान।

चर्चा में क्यों?

न्याय मत्तिर (Amicus Curiae) द्वारा संकलति आँकड़ों के अनुसार, 1 दसिंबर, 2021 तक देश भर की वभिन्नि अदालतों में वधायकों से जुड़े कुल 4,984 आपराधकि मामले लंबति थे।

- न्याय मत्तिर (Amicus Curiae) को सर्वोच्च न्यायालय ने सांसदों और वधायकों के खलिफ मामलों की त्वरति सुनवाई हेतु वशिष अदालतें स्थापति करने में मदद के लयि नयुक्ति कयिा था।
- यह प्रवृत्ति राजनीतिका अपराधीकरण की बढ़ती घटनाओं को उजागर करती है।
- न्याय मत्तिर (शाबदकि रूप से "अदालत का मत्तिर") वह व्यक्ती होता है जो किसी मामले में पक्षकार नहीं होता है तथा जो मामले में मुद्दों पर असर डालने वाली जानकारी, वशिषज्ञता या अंतरदृष्टि प्रदान करके अदालत की सहायता करता है।

राजनीतिका अपराधीकरण:

- इसका अर्थ राजनीति में अपराधियों की बढ़ती भागीदारी से है, जसिमें अपराधी चुनाव लड़ सकते हैं और संसद तथा राज्य वधायिका के सदस्य के रूप में चुने जा सकते हैं।
- यह मुख्य रूप से राजनेताओं और अपराधियों के बीच साँटगाँट के कारण होता है।

आपराधकि छवकि उम्मीदवारों की अयोग्यता का कानूनी पहलू:

- भारतीय संवधान में संसद या वधिानसभाओं के लयि चुनाव लड़ने वाले किसी आपराधकि प्रवृत्ति के व्यक्ती की अयोग्यता के वषिय में उपबंध नहीं कयिा गया है।
- लोक प्रतनिधित्व अधनियम, 1951 में वधायिका का चुनाव लड़ने के लयि किसी व्यक्ती को अयोग्य घोषति करने के मानदंडों का उल्लेख है।
 - इस अधनियम की धारा 8 ऐसे दोषी राजनेताओं को चुनाव लड़ने से नहीं रोकती है जनि पर केवल मुकदमा चल रहा है और दोष अभी सिद्ध नहीं हुआ है। इस बात से कोई फरक नहीं पड़ता कि उन पर लगा आरोप कतिना गंभीर है।
 - इस अधनियम की धारा 8(1) और 8(2) के अंतरगत प्रावधान है कयिदि कोई वधायिका सदस्य (सांसद अथवा वधायक) हत्या, बलात्कार, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने जैसे अपराधों में लपित है, तो उसे इस धारा के अंतरगत अयोग्य माना जाएगा एवं 6 वर्ष की अवधि के लयि अयोग्य घोषति कर दयिा जाएगा।

अपराधीकरण का कारण:

- कार्यान्वयन का अभाव: राजनीति में अपराधीकरण को रोकने के लयि बने कानूनों और नरिणयों के कार्यान्वयन की कमी के कारण इसमें बहुत मदद नहीं मलिी है।
- संकीर्ण स्वार्थ: राजनीतिक दलों द्वारा चुने गए उम्मीदवारों के संपूर्ण आपराधकि इतिहास का प्रकाशन बहुत प्रभावी नहीं हो सकता है, क्योंकि मतदाताओं का एक बड़ा हसिसा जातयिा धर्म जैसे सामुदायकि हतियों से प्रभावति होकर मतदान करता है।
- बाहुबल और धन का उपयोग: गंभीर आपराधकि पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के पास अक्सर धन और संपदा काफी अधिक मात्रा में होती है, इसलयि वे दल के चुनावी अभयिान में अधिक-से-अधिक पैसा खर्च करते हैं और उनकी राजनीति में प्रवेश करने तथा जीतने की संभावना बढ़ जाती है।

- इसके अतिरिक्त कभी-कभी तो मतदाताओं के पास कोई विकल्प नहीं होता है, क्योंकि सभी प्रतियोगी उम्मीदवार अपराधिक प्रवृत्तियों के होते हैं।

SC LEADS FIGHT TO CLEAN UP POLLS

CASES THAT LED TO THE RULINGS

2002 SC directs all candidates to file affidavit detailing their criminal antecedents, educational qualification and details of their assets. Upholds voters' right to know about a candidate's antecedents to make an informed choice (Association of Democratic Reforms)



(People's Union for Civil Liberties)

Mar | 2014 SC orders trial courts to hold **day-to-day trial in criminal cases** pending against sitting MPs and MLAs and complete it within one year from framing of charges

Aug SC recommends to **PM/CMs not to include persons**, against whom charges have been framed in serious offences, in their council of ministers (Manoj Narula)

July | 2013 SC quashes provision in Representation of the People Act that allowed MPs and MLAs to continue their membership in a House by merely filing appeal against their conviction and sentence of more than two years in a higher court. This meant **MPs and MLAs would be disqualified immediately on conviction and sentence of more than 2 years**. (Lily Thomas and Lok Prahari case)

Sept SC asks EC to provide **'none of the above' choice to voters** to exercise their right to express no confidence against all candidates in fray

Mar | 2016 SC refers to 5-judge Constitution bench whether **framing of charge in heinous crimes** (which entails imprisonment of five years or more) against an MP or MLA would disqualify him. This also meant—whether a person against whom charges framed in serious offences be debarred from contesting elections (Public Interest Foundation)



//

प्रभाव:

- **स्वतंत्र और नष्पिकष चुनाव के सिद्धांत के वरिद्ध:**
 - यह एक अच्छे उम्मीदवार का चुनाव करने के लिये मतदाताओं की पसंद को सीमित करता है।
 - यह स्वतंत्र और नष्पिकष चुनाव के लोकाचार के खिलाफ है जो कालोकांतर का आधार है।
- **सुशासन पर प्रभाव:**
 - प्रमुख समस्या यह है कि कानून तोड़ने वाले ही कानून बनाने वाले बन जाते हैं, इससे सुशासन स्थापित करने में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की प्रभावकारिता प्रभावित होती है।
 - भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली में यह प्रवृत्तियों के संस्थानों की प्रकृति तथा वधायिका के चुने हुए प्रतिनिधियों की गुणवत्ता की खराब छवियों को दर्शाती है।
- **लोक सेवकों के कार्य पर प्रभाव:**
 - इससे चुनावों के दौरान और बाद में काले धन का प्रचलन बढ़ जाता है, जिससे समाज में भ्रष्टाचार बढ़ता है तथा लोक सेवकों के काम पर असर पड़ता है।
- **सामाजिक भेदभाव को बढ़ावा:**
 - यह समाज में हिसा की संस्कृतियों को प्रोत्साहित करता है और भावी जनप्रतिनिधियों के लिये एक गलत उदाहरण प्रस्तुत करता है।

आगे की राह

- चुनाव सुधार पर बनी विभिन्न समितियों (दनिश गोस्वामी, इंदरजीत समिति) ने राज्य द्वारा चुनावी खर्च वहन किये जाने की सफारिश की, जिससे काफी हद तक चुनावों में काले धन के उपयोग पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी और परिणामस्वरूप राजनीतिक अपराधीकरण को सीमित किया जा सकेगा।
- एक स्वच्छ चुनावी प्रक्रिया हेतु राजनीतिक पार्टियों के मामलों को वनियमित करना आवश्यक है, जिसके लिये निर्वाचन आयोग (Election

Commission) को मज़बूत करना ज़रूरी है।

- मतदाताओं को चुनाव के दौरान धन, उपहार जैसे अन्य प्रलोभनों के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है।
- भारत के राजनीतिक दलों की राजनीतिक अपराधीकरण और भारतीय लोकतंत्र पर इसके बढ़ते हानिकारक प्रभावों को रोकने के प्रति अनिच्छा को देखते हुए यहाँ के न्यायालयों को अब गंभीर आपराधिक प्रवृत्ति वाले उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने जैसे फैसले पर विचार करना चाहिये।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/criminalization-of-politics-2>

